पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2021 का सिविल विविध क्षेत्राधिकार संख्या 73

==========

अनिल कुमार श्रीवास्तव, पुत्र स्वर्गीय डॉ. मुरली मनोहर, मुरली चंक, मेन रोड, थाना रफीगंज, जिला- औरंगाबाद-824125

.....याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. श्रीमती प्रेम लता श्रीवास्तव, विधवा स्वर्गीय निर्मल कुमार श्रीवास्तव, निवासी - 304, करपुरा मून पैलेस, चितकोहरा, डाक और थाना -अनीसाबाद, नगर और जिला - पटना
2. नीरज कुमार श्रीवास्तव, पुत्र स्वर्गीय बिमल कुमार श्रीवास्तव, निवासी सिमुलडीह (ताली फ़ारा) , डाकघर दामोदरपुर वाया आई. एस. एम., धनबाद, झारखंड, पिन-821004
3. संतोष कुमार श्रीवास्तव, पुत्र स्वर्गीय बिमल कुमार श्रीवास्तव, निवासी मोहल्ला चित्रा गोरा हीरापुर , रामधर सिंह के घर से बाईं लेन पर, धनबाद, झारखंड, पिन-826004, वर्तमान में चाणक्यगर, स्टील गेट, गोविंदपुर मेन रोड, पी. के. जी. आश्रम, थाना और जिला - धनबाद झारखंड, पिन-828109 में रहते हैं।
4. पंकज कुमार श्रीवास्तव, पुत्र स्वर्गीय बिमल कुमार श्रीवास्तव, निवासी मोहल्ला चित्रा गोरा हीरापुर , रामधर सिंह के घर से बाईं लेन पर, धनबाद, झारखंड, पिन-826004 वर्तमान में चाणक्यनगर, स्टील गेट, गोविंदपुर मेन रोड, पी. के. जी. आश्रम, थाना और जिला - धनबाद झारखंड, पिन-828109 में रहते हैं।
6. अखौरी प्रकाश कुमार, पुत्र स्वर्गीय दया कुमार, निवासी 219 पाटलिपुत्र कॉलोनी, पटना।
7. अखौरी सुभाष कुमार, पुत्र स्वर्गीय दया कुमार, निवासी 219 पाटलिपुत्र कॉलोनी, पटना।
8. अखौरी बिकाश कुमार, पुत्र स्वर्गीय दया कुमार, निवासी 219, पाटलिपुत्र कॉलोनी, पटना।
9. श्रीमती मधुलिका उर्फ मधु, पत्नी मुकुलजी, पुत्री दया कुमार, निवासी 219, पाटलिपुत्र

कॉलोनी, पटना।

10. डॉ. अनुपम लाल, पुत्र स्वर्गीय एस. के. लाल, निवासी 40, एम. आई. जी., हरदेव, भिलाई नगर, छत्तीसगढ़।

11. उत्तम लाल, पुत्र स्वर्गीय एस. के. लाल, निवासी 40, एम. आई. जी., हरदेव, भिलाई नगर, छत्तीसगढ़।

12. रेणु कुमार, पुत्री स्वर्गीय एस.के. लाल, निवासी 40, एम.आई.जी., हरदेव, भिलाई नगर, छत्तीसगढ़।

13. डॉ. रंजना वाधवा, पुत्री स्वर्गीय एस. के. लाल, निवासी 40, एम. आई. जी., हरदेव, भिलाई नगर, छत्तीसगढ़।

15. श्रीमती. आशा सिन्हा, पत्नी डी. एन. सिन्हा, क्वार्टर नं. 3025, सेक्टर 5 बी, बोकारो स्टील सिटी, जिला धनबाद, झारखंड।

16. विश्वनाथ प्रसाद, कुलदिप प्रसाद के पुत्र, निवासी रफीगंज, थाना रफीगंज, जिला-औरंगाबाद।

17. दीना नाथ प्रसाद, पुत्र कुलदीप प्रसाद, निवासी रफीगंज, थाना रफीगंज, जिला-औरंगाबाद।

.....प्रतिवादी

==========

उपस्थिति

याचिकाकर्ता/गण के लिए : श्री राय सौरभ नाथ, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के अधिवक्ता : श्री अंशुमन सिंह, अधिवक्ता

श्री रंजय कुमार, अधिवक्ता

==========

अधिनियम/धाराएं/नियम:

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXVI नियम 13, 14(1) और (2), 18

संदर्भित मामले:

पाबित्री देवी एवं अन्य बनाम रास बिहारी गोप एवं अन्य, 2010(2) पीएलजेआर 942 में रिपोर्ट किए गए

सिविल विविध क्षेत्राधिकार संख्या 337/2019

म.प्र. राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मर्यादित, पचामा, जिला सीहोर एवं अन्य बनाम मोदी ट्रांसपोर्ट सर्विस, (2022) 14 एससीसी 345 में रिपोर्ट किए गए

आसिफुनिसा एवं अन्य बनाम अली इमाम, 1992(1) पीएलजेआर 380 में रिपोर्ट किए गए

जगदीश भगत एवं अन्य बनाम श्री बैजनाथ राय एवं अन्य, 2007(3) पीएलजेआर 719 में रिपोर्ट किए गए

याचिका - उस आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई जिसके तहत ट्रायल कोर्ट ने Survey Knowing एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था।

वादी ट्रायल कोर्ट के समक्ष डिक्री धारक था जिसने संपत्ति के बंटवारे के लिए विभाजन वाद दायर किया था। विभाजन वाद को अनुमति दी गई। कोड के आदेश XXVI के नियम 13 के तहत दिए गए डिक्री के अनुसार विभाजन करने के लिए Survey knowing एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त किया गया था। एडवोकेट कमिश्नर ने पक्षों और अन्य स्वतंत्र व्यक्तियों की उपस्थिति में माप की ऑर्डर शीट पूरी की। जब कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई, तो एडवोकेट कमिश्नर ने अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार की और उसे ट्रायल कोर्ट में पेश किया।

निर्णय - यदि स्थिति ऐसी हो तो न्यायालय के पास पहले कमिश्नर की रिपोर्ट को रद्द करने के बाद दूसरे कमिश्नर को नियुक्त करने का अपेक्षित अधिकार है। इसलिए, अंतिम

तख्तबंदी रिपोर्ट को खारिज करने के न्यायालय के अधिकार को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती और इस आधार पर आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती। (पैरा 7)

ट्रायल कोर्ट ने आपत्ति पर विचार किया है और उसके बाद, विभिन्न दावेदारों के बीच संपत्ति के असमान वितरण पर विचार करते हुए, जब रिकॉर्ड में ऐसी असमानता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, तो ऐसी रिपोर्ट को बनाए रखना संभव नहीं है, भले ही एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट तैयार करते समय आपत्तियां न ली गई हों। यह तथ्य ट्रायल कोर्ट द्वारा विवादित आदेश पारित करते समय स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है, जब उसने देखा कि तख्तबंदी में मूल्यवान और उपयोगी वाणिज्यिक और आवासीय बहुमंजिला इमारत वादी के पक्ष में आवंटित की गई थी, जबकि सोन नदी के तल में बंजर भूमि प्रतिवादियों के पक्ष में आवंटित की गई थी। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि कुछ प्रतिवादियों को शेयर भी आवंटित नहीं किए गए थे। इन तथ्यों के आधार पर यदि ट्रायल कोर्ट एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को खराब पाता है और उसे खारिज कर देता है, तो यह न्यायालय ऐसे आदेश में हस्तक्षेप करने में सबसे अधिक अनिच्छुक होगा। (पैरा 7)

ट्रायल कोर्ट को तुरंत एक नए प्लीडर कमिश्नर की नियुक्ति के लिए आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया और यह भी निर्देश दिया गया कि प्लीडर कमिश्नर अपेक्षित समय के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। (पैरा 9)

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा
सीएवी निर्णय
तिथि - 07-01-2025

वर्तमान याचिका 2003 के विभाजन वाद संख्या 24 में विद्वान अवर न्यायाधीश द्वितीय, औरंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 14.10.2020 के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जहां और जिसके तहत विद्वान निचली अदालत ने अन्य राहत के अलावा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXVI नियम 14 (1) और (2) के तहत प्रस्तुत सर्वेक्षण जानने वाले अधिवक्ता आयुक्त की 21.10.2019 की रिपोर्ट को खारिज कर दिया।

2. संक्षेप में, अभिलेख से परिलक्षित तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता/वादी विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष डिक्री धारक था जिसने वाद की अनुसूची 1 से 4 की वाद संपत्ति के विभाजन के लिए 2003 का विभाजन मुकदमा संख्या 24 दायर किया था। 11.10.2018 पर, विभाजन मुकदमे की अनुमति दी गई और याचिकाकर्ता को 1/7 वें हिस्से का हकदार पाया गया। हालांकि, अनुसूची 3 और 4 को संयुक्त पारिवारिक संपत्ति नहीं माना गया था। तदनुसार, प्रारंभिक डिक्री को सील कर दिया गया और 27.10.2018 पर हस्ताक्षर किए गए और फैसले और डिक्री के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई। इसके बाद, सर्वेक्षण जानने वाले अधिवक्ता आयुक्त को संहिता के आदेश XXVI के नियम 13 के तहत दिए गए आदेश के अनुसार विभाजन करने के लिए नियुक्त किया गया था। 11.08.2019 पर, विद्वान अधिवक्ता आयुक्त ने पक्षों और अन्य स्वतंत्रत व्यक्तियों की उपस्थिति में माप का आदेश पत्र पूरा किया। 01.09.2019 पर, विद्वान अधिवक्ता आयुक्त ने सूट भूमि के रायबंदी का एक मसौदा तैयार किया और इसे 22.09.2019 पर तख्ता बंदी के मसौदे के साथ आपत्तियों के लिए नोटिस के साथ भेजा। जब कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई, तो विद्वान अधिवक्ता आयुक्त ने 21.10.2019 पर अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार की और संहिता के आदेश XXVI नियम 14 (2) के तहत

निर्धारित प्रक्रिया के संदर्भ में विद्वान निचली अदालत को 22.10.2019 पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रत्यर्थियों ने विद्वान अधिवक्ता आयुक्त द्वारा आवंटित तख्ते के खिलाफ अदालत के समक्ष 21.10.2019 पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। याचिकाकर्ता ने विद्वान अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट का समर्थन करते हुए 01.10.2020 पर अपना जवाब दाखिल किया। इसके बाद, विद्वान उप न्यायाधीश-II, औरंगाबाद ने 14.10.2020 पर आदेश पारित किया और विद्वान अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया। उक्त आदेश को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विद्वान निचली अदालत ने विद्वान सर्वेक्षण जानने वाले अधिवक्ता आयुक्त की दिनांकित 21.10.2019 रिपोर्ट को रद्द करने में स्पष्ट रूप से अवैधता की है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि विद्वान निचली अदालत ने विद्वान अधिवक्ता आयुक्त द्वारा पक्षकारों के पक्ष में दर्ज किए गए गुण-दोष के आधार पर निष्कर्ष पर विचार नहीं किया है। ज्ञात विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि प्रतिवादी विद्वान अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट पर आपत्ति नहीं उठा सकते थे क्योंकि उन्होंने संहिता के आदेश XXVI के नियम 18 के तहत उन पर जारी किए गए नोटिसों पर भी आयुक्त के समक्ष उपस्थित नहीं होने का विकल्प चुना और बाद में उनके समक्ष कोई आपत्ति भी नहीं उठाई। विद्वत विचारण न्यायालय को विद्वत अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट तैयार करने और स्वीकार करने में प्राकृतिक न्याय के नियमों को लागू नहीं करना चाहिए था क्योंकि उन्होंने पक्षकारों के मौन अनुमोदन के साथ रिपोर्ट तैयार करने और अंतिम रूप देने से पहले पक्षकारों को दो बार नोटिस दिया था। आदेश इस कारण से भी गलत है कि विद्वान अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट को उनकी रिपोर्ट के खिलाफ किसी भी आपत्ति पर उनकी जांच किए बिना और विद्वान अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट में गलती पाए बिना उनकी पीठ के पीछे खारिज कर दिया गया था। विद्वान वकील ने आगे दोहराया कि उत्तरदाताओं को विद्वान

अधिवक्ता आयुक्त के समक्ष अपनी आपत्ति रखनी थी और वे ऐसा करने में विफल रहे और प्रत्यर्थियों ने विद्वत अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट को विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष सीधे चुनौती दी। विद्वान वकील ने इस न्यायालय के माननीय एकल के निर्णय ***पबित्री देवी और अन्य का मामला बनाम रास बिहारी गोप और 2010 (2) पी. एल. जे. आर. 942*** का उल्लेख किया जिसमें इस मुद्दे पर रिपोर्ट की गई कि न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्यवाही में आदेश पत्रों को पवित्र माना जाना चाहिए। यदि किसी आदेश पत्र से पूछताछ की जाती है और आदेश का लेखक अपना बचाव करने की स्थिति में नहीं है तो आदेश पत्र में दर्ज आदेश प्रबल होगा। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि प्रतिवादियों ने अंतिम डिक्री की कार्यवाही में भाग लिया और परिणाम की प्रतीक्षा की और यदि उन्होंने विद्वान अधिवक्ता आयुक्त की मसौदा रिपोर्ट को चुनौती नहीं दी, तो उन्हें अंतिम रिपोर्ट और विद्वान अधिवक्ता आयुक्त के अधिकार क्षेत्र को भी चुनौती देने से रोक दिया जाता है। विद्वत अधिवक्ता आयुक्त की उनकी रिपोर्ट पर जांच के बिना, विद्वत निचली अदालत इसे खारिज नहीं कर सकती थी क्योंकि प्रतिवादियों ने विद्वत अधिवक्ता आयुक्त द्वारा अंतिम तख्त बंदी की तैयारी/सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं किया था, और यह पहली बार था जब प्रतिवादियों द्वारा उक्त याचिका उठाई गई थी। इस प्रकार, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विवादित निर्णय स्थायी नहीं है और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए।

4. प्रत्यर्थी संख्या 2, 16 और 17 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने दृढ़ता से तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश में कोई दोष नहीं है और इसके लिए वर्तमान कार्यवाही में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि ये उत्तरदाता मुकदमा दायर करने से पहले मुकदमे की संपत्ति के हिस्से के हस्तांतरणकर्ता हैं और वे उत्तरदाताओं को चुनौती दे रहे हैं क्योंकि अन्य उत्तरदाताओं को मामले में कोई रुचि नहीं है। अंतिम डिक्री कार्यवाही के परिणाम ने कथित रूप से

उन्हें हस्तांतरित की गई वाद संपत्ति में प्रतिवादियों के अधिकार और हित को सीधे प्रभावित करता यदि, उनके तर्क को ध्यान में नहीं रखा गया और इस तथ्य की पृष्ठभूमि में विद्वत निचली अदालत ने मामले में कार्यवाही की। विद्वान वकील ने आगे कहा कि वर्तमान सिविल विविध गलत है और अस्थिर है। विवादित आदेश कानून के अनुसार पारित किया गया है और विवादित आदेश में कोई अधिकार क्षेत्र की त्रुटियां नहीं है। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि जवाब देने वाले उत्तरदाताओं को नोटिस कभी नहीं दिए गए थे और यहां तक कि इस संबंध में याचिकाकर्ता का प्रस्तुत करना भी पूरी तरह से अस्पष्ट है क्योंकि याचिकाकर्ता का दावा है कि नोटिस नौ प्रतिवादियों को भेजे गए थे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि नौ प्रतिवादी कौन थे चुंकि प्रतिवादी नं. 6 जिनकी मृत्यु प्रारंभिक डिक्री, के पारित होने से पहले हुई थी और प्रतिवादी सं. 6 के उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों को ध्यान में रखते हुए कुल 14 प्रतिवादी इसलिए, 5 प्रतिवादियों को कोई नोटिस नहीं भेजा गया। इसके अलावा, गैर-उपस्थित प्रतिवादियों, यानी प्रतिवादी संख्या 7, 8 और 9 को कोई नोटिस नहीं भेजा गया है, जिनमें से प्रतिवादी संख्या 7 और 8 की प्रारंभिक आदेश पारित होने के बाद मृत्यु भी हो गई है। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि विद्वान अधिवक्ता आयुक्त ने विभिन्न संयुक्त मालिकों द्वारा बेचे गए शेयरों को ध्यान में नहीं रखा और रिपोर्ट वादी/याचिकाकर्ता के कहने पर तैयार की गई है और यह वादी/याचिकाकर्ता से प्रभावित एक पक्षपाती रिपोर्ट है। रिपोर्ट में कोई माप नहीं दिखाया गया है और सभी पक्षों की उपस्थिति में आयोजित नहीं किया गया था, जिनमें से कुछ को नोटिस भी जारी नहीं किया गया है। विद्वान अधिवक्ता आयुक्त के आदेश में कुछ गवाहों के पते का उल्लेख नहीं है और न ही मानचित्र पर उपस्थित पक्षों और गवाहों के हस्ताक्षर हैं। पूरी रिपोर्ट संदिग्ध है और निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत है। उक्त रिपोर्ट केवल एक तालिका रिपोर्ट है क्योंकि यह तथ्य विद्वान अधिवक्ता आयुक्त द्वारा कवर किए गए क्षेत्र से भी

पता चलता है। अभियोग की अनुसूची-1, 1(ए) और 2 में दी गई संपत्ति रफीगंज से दाउदनगर तक औरंगाबाद में स्थित है। रफीगंज और दाउदनगर के बीच की दूरी लगभग 50 किमी है और एक ही तिथि पर दो स्थानों पर वैज्ञानिक माप बनाना संभव नहीं था। विद्वान वकील ने आगे कहा कि जब नोटिस और तख्तबंदी का मसौदा विद्वान अधिवक्ता आयुक्त द्वारा सभी प्रतिवादियों को नहीं भेजा गया था, तो प्रतिवादी इस तरह के मसौदे पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कर सकते थे। प्रतिवादी संख्या 2, 16 और 17, जो धनबाद और रफीगंज में रह रहे हैं, उन्हें तख्तबंदी के मसौदे के बारे में पता चला और उन्होंने विद्वान अधिवक्ता आयुक्त को अपनी आपत्ति प्रस्तुत की। 21.10.2019 पर प्रस्तुत आपत्तियों को विद्वान अधिवक्ता आयुक्त द्वारा इस आधार पर स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया था कि उन्होंने पहले ही अंतिम तख्तबंदी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि 20.10.2019 रविवार था और उपरोक्त कारण से 20.10.2019 पर विद्वान अधिवक्ता आयुक्त के समक्ष आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की जा सकीं।

5. विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि रिपोर्ट के गुण-दोष पर भी, यह स्पष्ट है कि रिपोर्ट प्रारंभिक डिक्री के खिलाफ है क्योंकि विद्वत विचारण न्यायालय ने मुकदमे का फैसला सुनाते हुए कहा कि वादी अनुसूची-1, 1(ए) और 2 में उल्लिखित सभी संपत्तियों में 1/7 वें हिस्से का हकदार था, लेकिन वादी को अनुसूची-2 में उल्लिखित खाता संख्या 190, प्लॉट संख्या 1660/799/801, जो एक वाणिज्यिक-सह-आवासीय संपत्ति है, की पूरी संपत्ति आवंटित की गई है और जो वादी/याचिकाकर्ता के एक-सातवें हिस्से से अधिक है। विद्वान वकील ने दोहराया कि तख्तबंदी का मसौदा एकतरफा है क्योंकि सभी प्रतिवादियों को विद्वान अधिवक्ता आयुक्त द्वारा नोटिस नहीं दिए गए थे। अपनी रिपोर्ट में विद्वान अधिवक्ता आयुक्त ने खाता संख्या 190, प्लॉट संख्या 1660/799/801 की अनुसूची-2 भूमि की संपत्तियों का गलत मूल्यांकन किया

है, जो एक वाणिज्यिक-सह-आवासीय संपत्ति है और जिसका मूल्य डेढ करोड़ रुपये से अधिक है और सभी पक्ष इसमें हिस्सेदारी के हकदार हैं। दाउदनगर में अनुसूची-1 संपत्ति का हिस्सा बनने वाली 2 बीघा 16 कट्ठाओं के क्षेत्र वाली प्रतिवादियों को आवंटित भूमि एक बेकार, गैर-उपजाऊ बंजर भूमि है जो कृषि, आवासीय या किसी अन्य उद्देश्य के लिए अनुपयोगी है क्योंकि यह सोन नदी के तल पर स्थित है और इसका मूल्यांकन Rs.10,000/- प्रति बीघा से कम है। प्रतिवादी संख्या 1 और 8 ने अनुसूची 2 (i) संपत्ति में उल्लिखित वाद संपत्ति में अपना 7 वां हिस्सा पंजीकृत बिक्री विलेख संख्या 1497 दिनांक 05.02.2019 द्वारा एक मंगल लाल श्रीवास्तव को Rs.29,80,000/- के प्रतिफल के लिए बेच दिया। इस तथ्य के बावजूद, उक्त खरीदार को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था और उसे मुकदमे में पक्षकार नहीं बनाया गया था। इसलिए, रफीगंज के पूरे प्लॉट संख्या 799 और 801, खाता संख्या 190 को वादी को अनुमति देना पूरी तरह से अवैध है क्योंकि हस्तांतरणकर्ता को दाउदनगर में सूट संपत्ति में हिस्सा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा की गई आपत्ति कि उत्तरदाताओं द्वारा दायर आपत्तियों को हलफनामे के साथ समर्थित नहीं किया गया था, मामूली अनियमितता है और यह आपत्ति को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है। विद्वान वकील ने फिर से प्रस्तुत किया कि स्थानीय निरीक्षण कुछ प्रतिवादियों की पीठ के पीछे किया गया था जिन्हें विद्वान अधिवक्ता आयुक्त द्वारा नोटिस तक नहीं किया गया था। विद्वान वकील ने आगे कहा कि नोटिस की कोई सेवा नहीं दी गई है और भले ही उत्तरदाताओं के खिलाफ कोई अनुमान लगाया जाना था, लेकिन नोटिस जारी होने के 30 दिनों के बाद ही ऐसा किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान मामले में स्थानीय निरीक्षण 11.08.2019 पर किया गया है। यदि प्रतिवादियों को नोटिस जारी होने के 30 दिनों से पहले सेवा में घोषित किया गया था, तो जाहिर है कि उत्तरदाताओं पर कोई सेवा नहीं है। इसके बाद,

वादी की ओर से अन्य प्रतिवादियों की अनुपस्थिति में एक गुप्त निरीक्षण किया गया और मुकदमे की संपत्ति का कोई वैज्ञानिक माप नहीं किया गया है और न ही मुकदमे की संपत्ति का उचित मूल्यांकन किया गया है। उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील ने इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांकित 20.06.2019 ***सिविल विविध क्षेत्राधिकार संख्या 337 में पारित 2019*** का निर्णय का उल्लेख किया, जिसमें यह देखा गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 10 से 26 के उप-नियम (3) में यह प्रावधान है कि जहां न्यायालय किसी भी कारण से आयुक्त की कार्यवाही से असंतुष्ट है, वह ऐसी आगे की जांच करने का निर्देश दे सकता है जो वह उचित समझे और विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे कहा कि केवल इसलिए कि प्रतिवादियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को कायम रखा गया है और प्लीडर कमिश्नर की रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया है, आक्षेपित आदेश को गलत या विकृत नहीं माना जा सकता है। विद्वान वकील ने आगे एम. पी. राज्य तिलहन ***उत्पादक सहकारी संघ मर्यादा, पचामा, जिला सीहोर और अन्य बनाम मोदी परिवहन सेवा, (2022) 14 एस. सी. सी. 345*** में रिपोर्ट की गई के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय का उल्लेख किया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 34 से 37 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

> *"34. एक विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के महत्व और प्रभाव के संबंध में, दयाल सिंह बनाम उत्तरांचल राज्य मामले में इस न्यायालय का कहना है कि एक विशेषज्ञ राय का उद्देश्य मुख्य रूप से अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने में अदालत की सहायता करना है। ऐसी रिपोर्ट अदालत के लिए बाध्यकारी नहीं है। अदालत से उम्मीद की जाती है कि वह रिपोर्ट का विश्लेषण करेगी, इसे रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सबूतों के साथ पढ़ेगी और फिर अपनी अंतिम राय बनाएगी कि क्या ऐसी रिपोर्ट निर्भरता के*

योग्य है या नहीं। विधिवत सिद्ध एक विशेषज्ञ रिपोर्ट का अपना साक्ष्य मूल्य होता है, लेकिन इस तरह की प्रशंसा निर्धारित सीमाओं के भीतर और अदालत द्वारा सावधानीपूर्वक जांच के साथ होनी चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो, एक विशेषज्ञ गवाही देता है और निर्णय नहीं लेता है, उसका कर्तव्य अदालत को आवश्यक वैज्ञानिक/तकनीकी मानदंड प्रस्तुत करना है ताकि न्यायाधीश साक्ष्य में साबित तथ्यों पर इन मानदंडों को लागू करके अपना स्वतंत्रत निर्णय दे सके।

35. एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण और संहिता के आदेश 26 नियम 9 और 11 के तहत नियुक्त एक आयुक्त के दायरे और कार्यों के बीच भी अंतर है। मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के लिए, अधिनियम की धारा 21 के संदर्भ में एक मध्यस्थता समझौता या एक समझौता होना चाहिए कि उन पक्षों के बीच अंतर या विवाद जिसके लिए वे अर्ध-न्यायिक तरीके से निर्धारित करने का इरादा रखते हैं। आयुक्तों की नियुक्ति अदालत द्वारा की जाती है। नियुक्ति पक्षों की सहमति से या नियुक्ति पर आपत्ति होने पर भी हो सकती है। पूर्व-विद्यमान समझौता या यह आवश्यकता कि पक्ष न्यायालय के समक्ष सहमत हों, जैसा कि मध्यस्थता के मामले में अनिवार्य है, तब आवश्यक नहीं है जब कोई न्यायालय आयुक्त की नियुक्ति का निर्देश देता है। आयुक्त के प्रति निर्देश के मामले में, पक्षकार आयुक्त से संदर्भित विषय-वस्तु का मूल्यांकन/परीक्षण की अपेक्षा करते हैं, जो वह अपने कौशल, ज्ञान और अनुभव के अनुसार करेगा, जो बिना कोई सबूत लिए या तर्क सुने कर सकता है।

36. उपरोक्त निर्णयों के आलोक में, हम एक "सहायक" के सिद्धांत को

पेश करना चाहते हैं जिसे एक अदालत एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियुक्त कर सकती है, चाहे वह एक आयुक्त हो या एक विशेषज्ञ, और एक ऐसे तथ्य का पता लगाने का कारण बन सकता है जो विवादित भी हो सकता है। कुछ मामलों में, आयुक्त पक्षों को सुन सकता है और आयुक्त के समक्ष पक्षों द्वारा प्रस्तुत सामग्री या साक्ष्य के आधार पर अपनी विशेषज्ञ राय दे सकता है, जैसा कि इस मामले में जब अदालत ने एक चार्टर्ड एकाउंटेंट को नियुक्त किया था, जिसे एक विशेषज्ञ के रूप में लेखा पर बयान पर अपनी राय देने की आवश्यकता थी ताकि अदालत को एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण निर्णय पर पहुंचने में मदद मिल सके। यह अदालत का समय बचाने और अदालत के फैसले में देरी को कम करने के लिए था।

37. संहिता का आदेश 26 नियम 9 अदालत को स्थानीय जांच करने के लिए एक आयुक्त नियुक्त करने के लिए व्यापक शक्तियां देता है जो विवाद में किसी भी मामले को स्पष्ट करने, किसी भी संपत्ति के बाजार मूल्य, अपने लाभ या नुकसान के खाते या वार्षिक शुद्ध लाभ का पता लगाने के लिए आवश्यक या उचित हो सकती है। आदेश 26 नियम 11 के तहत, अदालत के पास एक मुकदमे में आयोग जारी करने की शक्ति है, जिसमें किसी व्यक्ति के लिए खातों का समायोजन आवश्यक है, क्योंकि वह उचित समझता है और उसे ऐसी जांच या समायोजन करने का निर्देश देता है। जब कोई अदालत ऐसे व्यक्ति को ऐसा आयोग जारी करती है, तो वह आयुक्त को इस तरह की जांच, जांच और समायोजन करने और अदालत को उस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है। इस प्रकार नियुक्त आयुक्त सख्ती से "न्यायिक कार्य जो

बाध्यकारी है" नहीं करता है, बल्कि केवल एक "मंत्रिस्तरीय कार्य" करता है। आयुक्त के विवेक पर कुछ भी नहीं छोड़ा जाता है, और अपने निर्णय का उपयोग करने या आयुक्त को शामिल मुद्दे पर निर्णय लेने और निर्णय लेने की अनुमति देने का कोई अवसर नहीं है; आयुक्त की रिपोर्ट केवल एक राय या टिप्पणी है, जैसा कि मामला विवरण और/या अदालत को वास्तविक स्थिति के बयान के साथ हो सकता है। इस तरह की रिपोर्ट स्वचालित रूप से अदालत की राय का हिस्सा नहीं बनती है, क्योंकि अदालत के पास रिपोर्ट की पुष्टि करने, उसमें बदलाव करने या उसे दरकिनार करने या किसी मामले में एक नया आयोग जारी करने की शक्ति है। इसलिए, इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए न तो त्याग किया जाता है और न ही न्यायालय के कार्यों की शक्तियों का प्रत्यर्पण किया जाता है। कभी-कभी, आयुक्त की जांच पर, रिपोर्ट रिकॉर्ड और साक्ष्य का हिस्सा बनती है। पक्ष एक विशेषज्ञ राय/आयुक्त की रिपोर्ट को चुनौती दे सकते हैं, और अदालत, आपत्तियों को सुनने के बाद, यह निर्धारित कर सकती है कि उसे ऐसे विशेषज्ञ की राय/आयुक्त की रिपोर्ट पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। भले ही न्यायालय उसी पर निर्भर करता है, यह केवल सहायता करेगा और न्यायालय को बाध्य नहीं करेगा। सख्त अर्थों में, आयुक्तों की रिपोर्ट "गैर-न्यायिक प्रकृति की होती हैं", और अदालतें पक्षों के अधिकारों पर निर्णय देती हैं।

विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि न्यायिक आयुक्त का कार्य एक मंत्रिस्तरीय कार्य है और यह एक न्यायिक कार्य नहीं है जो बाध्यकारी हो और यह अदालत के विवेक पर छोड़ दिया जाता है कि वह ऐसी रिपोर्ट पर भरोसा करेगा या नहीं। विद्वान वकील ने आगे मामले में इस न्यायालय के ***आसिफुन्निसा और एक अन्य बनाम***

अली इमाम, 1992 में रिपोर्ट ***(1) पी. एल. जे. आर. 380*** के पूर्ण पीठ के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें माननीय पूर्ण पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसे मामले में जहां अदालत को पता चलता है कि रिपोर्ट अमान्य है या अन्यथा अनुचित रूप से प्राप्त की गई है या उसमें आयुक्त ने अदालत के निर्देशों का पालन नहीं किया है, ऐसी रिपोर्ट साक्ष्य में अस्वीकार्य होगी और इस प्रकार अदालत को उक्त रिपोर्ट को दरकिनार करने की अंतर्निहित शक्ति के रूप में अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए और इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया कि यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी भी परिस्थिति में, अदालत को रिपोर्ट को दरकिनार करने का कोई अधिकार नहीं होगा और इस स्थिति में, अदालत को न केवल अपेक्षित अधिकार क्षेत्र है, बल्कि ऐसी रिपोर्ट को दरकिनार करने और एक अन्य प्लीडर कमिश्नर द्वारा स्थानीय निरीक्षण कराए जाने का निर्देश देने का कर्तव्य भी है। विद्वान वकील ने ***जगदीश भगत तथा अन्य बनाम श्री बैजनाथ राय और अन्य 2007 (3) पी. एल. जे. आर. 719*** में रिपोर्ट किया गया**,** के मामले में इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय का भी उल्लेख किया है।

पैराग्राफ 16 और 17 को नीचे पढ़ा गया हैः- .

> *“16. पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने और अचल संपत्ति का विभाजन करने के लिए आयोग से संबंधित आदेश 26 नियम 13 और 14 के साथ स्थानीय जांच के लिए आयोग से संबंधित सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 नियम 9 और 10 के प्रावधानों के तुलनात्मक विश्लेषण पर, इस अदालत का विचार है कि ये दो प्रकार के आयोग स्पष्ट रूप से अलग-अलग आधार पर खड़े हैं। जहाँ तक विभाजन करने के लिए आयोग का संबंध है, यह अदालत का दायित्व है कि वह पक्षकारों के अलग-अलग हिस्से को बनाने के लिए प्लीडर कमिश्नर द्वारा दायर की गई रिपोर्ट या रिपोर्ट की पुष्टि करे या उसे दरकिनार करे। यदि योग्यता*

के आधार पर इसकी पुष्टि की जाती है, तो निश्चित रूप से विभाजन मुकदमे में अंतिम डिक्री प्लीडर कमिश्नर की ऐसी रिपोर्ट के संदर्भ में तैयार की जाती है, जिसकी पुष्टि नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा योग्यता के आधार पर की जाती है।

17. जहाँ तक स्थानीय जाँच आयोग का संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि इस तरह के कमीशन को केवल मुकदमे में एक सबूत के रूप में माना जा सकता है और यह विभाजन मुकदमे में प्लीडर कमिश्नर की रिपोर्ट के समान नहीं है। हालाँकि, किसी भी पक्ष को एक महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है कि वह प्लीडर कमिश्नर की रिपोर्ट पर आपत्ति उठाए और अदालत की अनुमति से, कमिश्नर से व्यक्तिगत रूप से खुली अदालत में पूछताछ करे, जिसमें उन्हें संदर्भित या उनकी रिपोर्ट में उल्लिखित किसी भी मामले को छुआ जाए, या उनकी रिपोर्ट के बारे में या जिस तरीके से उन्होंने जांच की है। आदेश 26 नियम 10 उप नियम (3) में आगे स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि जहां न्यायालय किसी भी कारण से आयुक्त की कार्यवाही से असंतुष्ट है, वह आगे ऐसी जांच करने का निर्देश दे सकता है जो वह उचित समझे। उक्त प्रावधान की व्याख्या इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने निचली अदालत को या तो प्लीडर कमिश्नर की रिपोर्ट को स्वीकार करने या यहां तक कि इसे दरकिनार करने के लिए एक निश्चित अधिकार प्रदान करने के रूप में की है। ऊपर उद्धृत पूर्ण पीठ के निर्णय में आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक बार जब अदालत प्लीडर कमिश्नर की रिपोर्ट को खारिज कर देती है तो उसके पास दूसरा आयोग नियुक्त करने की शक्ति होती है और न केवल यह कि उसके पास ऐसा

अधिकार क्षेत्र है, बल्कि ऐसी रिपोर्ट को अलग करने और किसी अन्य प्लीडर कमिश्नर द्वारा स्थानीय निरीक्षण करने का निर्देश देंने का कर्तव्य भी है।

उपरोक्त निर्णयों के बल पर, विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया कि पक्षकारों को सुनने के बाद और प्रतिवादियों की वास्तविक और वैध आपत्ति पर विचार करने के बाद, मन के उचित प्रयोग के बाद विवादित आदेश पारित किया गया है और विवादित आदेश कानून के अनुरूप है विवादित आदेश में कोई अवैधता नहीं है जो पूरी तरह से कानूनी है और इसमें कोई अधिकार क्षेत्र की त्रुटियां नहीं दिखाई देती है और इसलिए, इस न्यायालय द्वारा विवादित आदेश को बनाए रखने की आवश्यकता है।

6. याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब के माध्यम से प्रस्तुत किया कि विद्वान अधिवक्ता आयुक्त को चुनाव लड़ने वाले पक्ष की उपस्थिति में नियुक्त किया गया था और नोटिस पर, प्रतिवादी उनके सामने पेश हुए। उत्तरदाता संख्या 2, 16 और 17 को विधिवत नोटिस जारी किए गए थे। जवाब देने वाले प्रतिवादी अन्य प्रतिवादियों को नोटिस न दिए जाने की कहानी बनाकर इस न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार, उत्तरदाताओं के पास विद्वान अधिवक्ता आयुक्त के समक्ष आपत्ति दर्ज करने का पर्याप्त अवसर था, लेकिन वे अंतिम तख्तबंदी तक चुप रहे। यहां तक कि दायर की गई आपत्ति भी बिना किसी दावे के है कि विद्वान अधिवक्ता आयुक्त ने उनकी आपत्ति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब उत्तरदाताओं के दावे की बात आती है अर्ध न्यायिक कार्यवाही का आदेश पत्र प्रबल होगा और विद्वान अधिवक्ता आयुक्त के आदेश पत्र से यह स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं को जानकारी थी कि विद्वान अधिवक्ता आयुक्त आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने अंतिम तख्तबंदी कार्यवाही में भाग नहीं लिया। इसके अलावा, यदि इस स्तर पर विद्वान अधिवक्ता आयुक्त के आदेश पत्र पर सवाल उठाया जाता है, तो वह अपना बचाव करने की स्थिति में नहीं है। विद्वान वकील ने

जोरदार ढंग से तर्क दिया कि यदि जवाब देने वाले प्रतिवादी विद्वान अधिवक्ता आयुक्त के सामने एक दिन के लिए भी पेश होते हैं, जैसा कि उनके प्रस्तुतिकरण से प्रतीत होता है, तो उन्हें अन्य प्रतिवादियों पर नोटिस की सेवा के संबंध में कोई याचिका दायर करने से रोक दिया जाता है। विद्वान वकील ने दोहराया कि पूरी आपत्ति याचिका बिना किसी हलफनामे के है और इस तथ्य पर चुप है कि प्रतिवादियों ने विद्वान अधिवक्ता आयुक्त के समक्ष अंतिम तख्तबंदी की तैयारी में सुधार के लिए कोई प्रयास किया है। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि विद्वत निचली अदालत इन सभी तथ्यों की सराहना करने में विफल रही और आगे यह विचार करने में विफल रही कि प्रतिवादी सर्वेक्षण कार्यवाही से अनुपस्थित नहीं थे और रिपोर्ट की वास्तविकता पर अधिवक्ता आयुक्त की जांच के बिना, विवादित आदेश गलत तरीके से पारित किया गया है। इसके अलावा, हलफनामे का समर्थन किए बिना किसी भी कार्यवाही में विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष दायर किया जा सकता है। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि उत्तरदाताओं की पूरी आपत्ति इस तथ्य पर आधारित है कि संपत्तियों का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया था और यह कहीं भी नहीं कहता है कि गैर-उपस्थित उत्तरदाताओं को नोटिस नहीं दिए गए थे। इस प्रकार, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विवादित आदेश अवैध है और टिकाऊ नहीं है और इसके लिए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

7. मैंने पक्षों के प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतिकरण पर विचारपूर्वक विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है। स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान का उल्लेख करना फायदेमंद होगा। आदेश 26 नियम 9, 10, 13 और 14 वर्तमान मामले पर विचार करने के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक हैं। प्रावधानों को निम्नानुसार पढ़ा जाता हैः

9. स्थानीय जाँच-पड़ताल के लिए आयोग-- *किसी भी वाद में जिसमें*

न्यायालय किसी विवादग्रस्त मामले को स्पष्ट करने, या किसी संपत्ति के बाजार-मूल्य, या किसी भी महत्वपूर्ण लाभ या क्षति या वार्षिक शुद्ध लाभ की राशि का पता लगाने के उद्देश्य से स्थानीय जांच को आवश्यक या उचित समझता है, न्यायालय ऐसे व्यक्ति को एक आयोग जारी कर सकता है जो उसे उचित लगे और उसे ऐसा निर्देशित करते हुए कि वह ऐसी जांच करें और उसकी रिपोर्ट कोर्ट को दें का निर्देश दे सकता है| बशर्ते कि, जहां राज्य सरकार ने उन व्यक्तियों के बारे में नियम बनाए हैं जिन्हें ऐसा आयोग जारी किया जाएगा, वहां न्यायालय ऐसे नियमों से बाध्य होगा।

***10. आयुक्त की प्रक्रिया**-- (1) आयुक्त, ऐसे स्थानीय निरीक्षण के बाद, जो वह आवश्यक समझता है और अपने द्वारा लिए गए साक्ष्य को लिखने के बाद, अपने द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रिपोर्ट के साथ ऐसे साक्ष्य को न्यायालय को वापस करेगा।*

*(2) **सूट में साक्ष्य के रूप रिपोर्ट और बयान**-- आयुक्त का प्रतिवेदन और उसके द्वारा लिया गया साक्ष्य (लेकिन प्रतिवेदन के बिना साक्ष्य नहीं) वाद में साक्ष्य होगा और अभिलेख का हिस्सा होगा; लेकिन न्यायालय या न्यायालय की अनुमति से वाद का कोई भी पक्ष, आयुक्त को निर्दिष्ट या उसकी रिपोर्ट में उल्लिखित किसी भी मामले को, या उसकी रिपोर्ट के बारे में, या जिस तरीके से उसने जाँच की है, उसके बारे में खुले न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से जाँच कर सकता है।*

*(3) **आयुक्त की जाँच व्यक्तिगत रूप से की जा सकती है**--जहां न्यायालय किसी भी कारण से आयुक्त की कार्यवाहियों से असंतुष्ट है, वह ऐसी आगे की जांच करने का निर्देश दे सकता है जो वह उचित समझे।*

13. अचल संपत्ति का विभाजन करने के लिए आयोग--*जहाँ एक प्रारंभिक विभाजन के लिए डिक्री पारित कर दी गई है, न्यायालय, किसी भी मामले में धारा 54 द्वारा प्रदान नहीं किया गया है, ऐसे व्यक्ति को एक कमीशन जारी कर सकता है जो उस डिक्री में घोषित अधिकारों के अनुसार विभाजन या अलगाव करने के लिए उचित समझता है।*

14. आयुक्त की प्रक्रिया-- *(1) आयुक्त, ऐसी जांच के बाद, जो आवश्यक हो, संपत्ति को उतने शेयरों में विभाजित करेगा जो उस आदेश द्वारा निर्देशित किए जा सकते हैं जो आयोग द्वारा जारी किया गया था, और ऐसे शेयरों को पक्षों को आवंटित करेगा, और यदि उक्त आदेश द्वारा उन्हें अधिकृत किया जाता है, तो शेयरों के मूल्य को बराबर करने के उद्देश्य से भुगतान की जाने वाली राशियों का अधिनिर्णय कर सकता है।*

(2) आयुक्त तब एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा या आयुक्त (जहां आयोग एक से अधिक व्यक्तियों को जारी किया गया था और वे सहमत नहीं हो सकते हैं) प्रत्येक पक्ष के हिस्से को नियुक्त करने और प्रत्येक हिस्से (यदि ऐसा उक्त आदेश द्वारा निर्देशित किया गया है) में अंतर करने के लिए अलग-अलग रिपोर्ट तैयार करेंगे और हस्ताक्षर करेंगे। ऐसी रिपोर्ट या रिपोर्ट आयोग के साथ संलग्न की जाएगी और अदालत को प्रेषित की जाएगी; और अदालत; किसी भी आपत्ति को सुनने के बाद जो पक्ष रिपोर्ट या रिपोर्ट पर कर सकते हैं, की पुष्टि, परिवर्तन या दरकिनार कर देगा।

(3) जहां न्यायालय रिपोर्ट या रिपोर्ट की पुष्टि या परिवर्तन करता है, वह उसी के अनुसार एक डिक्री पारित करेगा जिसकी पुष्टि या परिवर्तन होता है; लेकिन जहां न्यायालय रिपोर्ट या रिपोर्ट को दरकिनार करता है, वह

या तो एक नया आयोग जारी करेगा या ऐसा अन्य आदेश देगा जो वह उचित समझेगा।

उपरोक्त प्रावधान के एक संयुक्त पठन से यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि अदालत के पास पहले आयुक्त की रिपोर्ट को दरकिनार करने पर यदि स्थिति ऐसी है तो दूसरा आयुक्त नियुक्त करने की आवश्यक शक्ति है । इसलिए, अंतिम तख्तबंदी रिपोर्ट को अस्वीकार करने के लिए अदालत के अधिकार को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती थी और इस आधार पर आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती थी। ***एम. पी. राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मर्यादा, पचामा, जिला सीहोर और अन्य बनाम मोदी परिवहन सेवा, आसिफुनिसा और एक अन्य बनाम अली इमाम और जगदीश भगत और अन्य बनाम श्री बैजनाथ राय और अन्य*** *(ऊपर)* के मामलों में उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा मामलों पर भरोसा किया गया जो इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक कार्यवाही में, यह न्यायालय आम तौर पर मामले के तथ्यात्मक पहलुओं में प्रवेश करने से बचता है जब तक कि अधीनस्थ अदालतों की ओर से कोई विकृति या अवैधता या अधिकार क्षेत्र की त्रुटियां न हो। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का मुख्य तर्क उत्तरदाताओं को नोटिस की सेवा और उत्तरदाताओं द्वारा विद्वान एडवोकेट कमिश्नर के समक्ष कार्यवाही में भाग नहीं लेने के संबंध में है। विद्वत विचारण न्यायालय ने आपत्ति को ध्यान में रखा है और उसके बाद, विभिन्न दावेदारों के बीच संपत्ति के अन्यायपूर्ण वितरण पर विचार करते हुए, जब ऐसी असमानता रिकॉर्ड के सामने बड़ी होती है, तो इस तरह की रिपोर्ट को बनाए रखना संभव नहीं है, भले ही विद्वत अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट तैयार करते समय आपत्तियों को नहीं लिया गया हो। विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा विवादित आदेश पारित करते समय इस तथ्य को स्पष्ट किया गया है जब उसने पाया कि मूल्यवान और उपयोगी वाणिज्यिक और आवासीय बहुमंजिला इमारत तख्तबंदी में वादी

के पक्ष में आवंटित की गई थी, जबकि सोन नदी के तल में बंजर भूमि प्रतिवादियों के पक्ष में आवंटित की गई थी। यह भी दलील किया गया है कि कुछ प्रतिवादियों को हिस्सा भी आवंटित नहीं किए गए थे। इन तथ्यों के आधार पर यदि विद्वत विचारण न्यायालय विद्वत अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट को गलत पाता है और उसे खारिज कर देता है, तो यह न्यायालय ऐसे आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए सबसे अधिक अनिच्छुक होगा।

8. इसलिए, उपरोक्त चर्चा के आलोक में, मुझे दिनांकित 14.10.2020 विद्वत विचारण न्यायालय के द्वारा पारित किया गया आदेश में कोई दुर्बलता या अधिकार क्षेत्र की त्रुटियां नहीं मिलती है। और इसलिए, इसकी पुष्टि की जाती है। तदनुसार, वर्तमान याचिका योग्यता से रहित होने के कारण खारिज कर दी जाती है।

9. हालांकि, विद्वत निचली अदालत को एक नए प्लीडर कमिश्नर की नियुक्ति के लिए तुरंत आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाता है और यह आगे निर्देश दिया जाता है कि विद्वत प्लीडर कमिश्नर अंतिम तख्तबंदी के संबंध में पक्षों की आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद नियुक्ति की तारीख से एक महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति)

डीकेएस/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।